वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, सी. आर. बी. कैपिटल मार्कट्स लि॰ में विभिन्न संस्थाओं का एक्सपोजर लगभग 152 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कम्पनी ने 186 करोड़ रुपए की राशि की 1,30,000 से अधिक सावधि जमा रसीदें जारी की थीं। ये आंकड़े अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार हैं और वे पूर्णरूपेण अनन्तिम तथा आगे पुष्टि के अध्यधीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एमसी के अन्तर्गत एक परिसमापन याचिका दायर की है। उच्च-न्यायालय ने एक अनन्तिम सरकारी परिसमापक की नियुक्ति का आदेश दिया है, जिसने कम्पनी की आस्तियों और देयताओं का निर्धारण करने के उपाय शुरू कर दिए हैं।

(ख) सरकार ने विनियामकों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) से कहा है कि वे सी॰ आर॰ बी॰ समूह की कंपनियों पर विनियमों को लागू करने या चेतावनी संकेतों का उत्तर देने में हुई किसी प्रकार की चूक को देखने के लिए इन कम्पनियों के संबंध में विनियामक कार्यों की पूर्णरूपेण आंतरिक पुनरीक्षा करें ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके।

(ग) और (घ) भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) के अनुसार, जी॰ आई॰ सी॰ म्युचुअल फंड के न्यासियों ने, जी॰ आई॰ सी॰ म्युचुअल फंड द्वारा भारत के सीलिस्टिर जनरल से ली गई कानूनी राय के अनुसार जी. आई. सी. बिग वैल्यू स्कीम के यूनिटधारकों को आश्वासित प्रतिफल (एस्थोर्ड रिटर्न) के भुगतान की प्रतिबद्धता को सकारने का निर्णय लिया है। आश्वासित दर पर यूनिटों का मोचन 30 जून, 1997 को किया जाना था और फंड द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से इस संबंध में यूनिटधारकों को सूचना दे दी गई है।

Proposal to review the Open Sky Policy

*94. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to review its Open Sky policy and permit foreign airlines to operate within the country freely as suggested by the Prime Minister during his recent visit to Kathmandu; and

(b) if so, by when the review is likely to be accomplished and if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) There is a proposal to frame a comprehensive national policy on civil aviation, encompassing all aspects. This will be framed within the next three months. There is, however, no proposal to permit foreign airlines to hold equity in domestic airlines.

Draft Aviation Policy

*95. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA:
SHRI MAHESHWAR SINGH:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-report entitled "Yes, there is a draft aviation policy" published in the Indian Express, New Delhi, dated July 3, 1997;

(b) whether Government has denied reports that any new draft aviation policy had either been prepared or circulated among officials to elicit their views; and

(c) if so, the reasons why Government resorted to issue a false denial?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) The reports in the media had suggested that a draft policy on civil aviation had been prepared by Secretary, Civil Aviation and circulated among the junior officials. They also stated that this draft policy sought to reverse an earlier Cabinet decision banning investment by foreign airlines in the equity of domestic airlines.

The factual situation is that officials in the Ministry had been asked to prepare suggestions for consideration, so that these could be finalised after discussion in a comprehensive document. One of the several inputs to that document was a paper prepared by DGCA which was circulated, like the other papers, among officials of the Ministry. It could, by no stretch of the imagination, be called a draft policy document prepared by Secretary, Civil